



27 March, 2024

मशीन-टू-मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम का उपयोग

संदर्भ: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में मशीन-टू-मशीन (M2M) संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विस्तार क्षेत्र और महत्व:

- देश में 5जी सेवाओं के आगमन ने एम2एम पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का काफी विस्तार किया है।
- एम2एम प्रौद्योगिकी में प्रगति से कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक स्वचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होगा।
- इस विस्तार का उद्देश्य भारत में एम2एम एम्बेडेड सिम (ई-सिम) उपयोग के लिए एक सामंजस्यपूर्ण नियामक ढांचा स्थापित करना है, जो विकसित दूरसंचार परिदृश्य के साथ संरेखित है।

मुख्य प्रावधान:

- रूपांतरण अधिदेश:** भारत में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के दौरान एम2एम (ई-सिम) को छह महीने के भीतर भारतीय टीएसपी प्रोफाइल पर स्विच करना होगा।
- लाइसेंस धारक अनुमतियाँ:** विशिष्ट लाइसेंस धारक भारत में एसएम-एसआर संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं।
- प्रोफाइल स्थापना लचीलापन:** ओईएम और एम2एमएसपी भारतीय टीएसपी के एसएम-डीपी से प्रोफाइल डाउनलोड विधियां चुन सकते हैं।
- एकीकरण अधिदेश:** एसएम-एसआर को अनुरोध के आधार पर तीन महीने के भीतर लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार प्रदाताओं के एसएम-डीपी के साथ एकीकृत करना होगा।
- एसएम-एसआर स्विचिंग सुविधा:** एम2एमएसपी को अनुरोध के आधार पर छह महीने के भीतर एसएम-एसआर स्विचिंग की सुविधा देनी होगी।
- आईएमएसआई श्रृंखला निषेध:** कार्यान्वयन चुनौतियों के कारण भारत में एम2एम सेवाओं के लिए 901.XX आईएमएसआई श्रृंखला का उपयोग प्रतिबंधित है।

एम्बेडेड सिम (ई-सिम)

ई-सिम का अवलोकन:

- ई-सिम, या एम्बेडेड सिम, एक सिम कार्ड है जो सीधे डिवाइस में एम्बेड (संस्थापित) किया जाता है, जिसमें eUICC चिप पर इंस्टॉल किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है।
- पारंपरिक सिम कार्ड के विपरीत, ई-सिम को नई सिम जानकारी के साथ फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है यदि वे eUICC-संगत हों।

विकास और मानकीकरण:

- जीएसएमए ने वर्ष 2010 में सॉफ्टवेयर-आधारित सिम की अवधारणा पेश की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 में ईएसआईएम मानक जारी हुआ।
- वर्तमान में इस मानक के दो संस्करण मौजूद हैं: एक उपभोक्ता उपकरणों के लिए और दूसरा मशीन-टू-मशीन (एम2एम) उपकरणों के लिए।

डिज़ाइन और उपयोग:

- एक पारंपरिक सिम कार्ड मैनुअल रूप से एक डिवाइस में डाला जाता है, जबकि एक ई-सिम एक वचुअलाइज्ड सिम कार्ड प्रोफाइल है, जो फ़ैक्ट्री में एक डिवाइस पर स्थायी रूप से सतह पर लगे eUICC चिप पर इंस्टॉल होता है।
- एक बार ई-सिम कैरियर प्रोफाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद, यह एक अद्वितीय ICCID और नेटवर्क प्रमाणीकरण कुंजी के साथ, एक भौतिक सिम के समान ही काम करता है।

दूरस्थ प्रावधान और कनेक्टिविटी:

- ई-सिम को दूरस्थ रूप से प्रावधानित किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता सिम कार्ड को भौतिक रूप से स्वीप किए बिना विभिन्न ऑपरेटरों को जोड़ या हटा सकते हैं।
- सभी ई-सिम को फ़ैक्ट्री में एक स्थायी ई-सिम आईडी (EID) के साथ प्रोग्राम किया जाता है, जिससे प्रावधान और सुरक्षित चैनल संपर्क की सुविधा मिलती है।

अनुप्रयोग और कार्यान्वयन:

- ई-सिम तकनीक विभिन्न IoT परिदृश्यों में अनुप्रयोग ढूंढती है, जिसमें कनेक्टेड कार, स्मार्ट डिवाइस, जीपीएस ट्रैकिंग यूनिट इत्यादि शामिल हैं।

- ईयूआईसीसी चिप के सामान्य भौतिक रूप कारकों में एमएफएफ2 शामिल है, जिसमें यूरोपीय आयोग की ई-कॉल सेवा और रूस की ईआए-ग्लोनास पहल जैसे कार्यान्वयन भी शामिल हैं।

लाभ/गुण:

- इसमें एक साथ कई सिम स्टोर किए जा सकते हैं।
- भौतिक सिम कार्ड प्राप्त करने, संग्रहीत करने और डालने/निकालने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- "मेरा फ़ोन ढूँढें" सेवाओं के माध्यम से यह चोरी हुए फ़ोन की ट्रैकिंग सक्षम करता है।
- ई-सिम तकनीक के उपयोग से सिम सॉफ़्ट संपर्कों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम समाप्त हो जाता है।
- केवल ई-सिम क्षमता वाले उपकरणों को हार्डवेयर सिम धारकों की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्मार्टवॉच जैसे कॉम्पैक्ट उपकरणों के लिए आदर्श है।

हानि/दोष:

- यदि फ़ोन टूटा हुआ है तो नेटवर्क संसाधन पहुंच योग्य नहीं हैं, क्योंकि कॉल प्राप्त नहीं की जा सकती हैं और भुगतान किए गए संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- मरम्मत के लिए या दूसरों को फ़ोन उधार देते समय ई-सिम निकालने में असमर्थता होती है।
- स्विच ऑन करने पर फ़ोन की लोकेशन की लगातार ट्रैकिंग की जा सकती है।
- बेचे गए या नष्ट हो चुके फ़ोन से ई-सिम खातों को हटाने या स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- कुछ फ़ोनों के साथ संगतता संबंधी समस्याएँ भी होती हैं, जैसे अमेरिकी डिवाइस अन्य देशों से ई-सिम स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024

संदर्भ: हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की पृष्ठभूमि:

- यह रिपोर्ट श्रम और रोजगार के मुद्दों पर मानव विकास संस्थान की श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है।
- यह युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वर्ष 2000 से 2023 तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और अन्य स्रोतों से डेटा का विश्लेषण करता है।
- यह रिपोर्ट दो दशकों में आर्थिक, श्रम बाजार, शैक्षिक और कौशल परिदृश्यों में बदलाव की जांच करता है।

रोजगार के रुझान और वर्तमान परिदृश्य:

- वर्ष 2019 तक श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर में दीर्घकालिक गिरावट देखी गई, उसके बाद सुधार हुआ।
- महिला श्रम बाजार भागीदारी दर में वर्ष 2019 के बाद से आवश्यक सुधार देखा गया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- वर्ष 2005 और वर्ष 2022 के बीच रोजगार की स्थितियों में समग्र सुधार देखस गया, हालांकि वर्ष 2019 के बाद COVID-19 महामारी के कारण रुक गया।
- कृषि से गैर-कृषि रोजगार की ओर धीमा संक्रमण वर्ष 2019 के बाद विपरीत देखा गया, जिससे कृषि रोजगार में वृद्धि हुई।
- मुख्य रूप से महिलाओं के बीच स्व-रोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि देखी गई।
- अनौपचारिक क्षेत्र में स्थिर या घटती मजदूरी और निम्न आय के साथ निम्न गुणवत्ता वाले रोजगार का प्रभुत्व देखा गया।

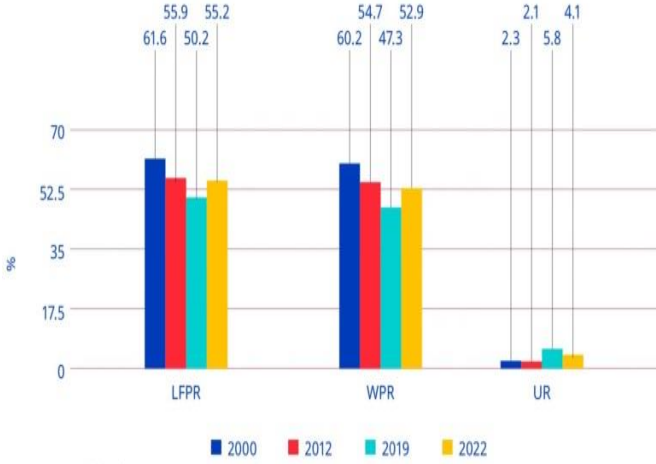
Face to Face Centres





27 March, 2024

► Figure 2.1. Labour force participation rate, worker population ratio and unemployment rate (UPSS) among persons aged 15+ (rural and urban combined), 2000, 2012, 2019 and 2022 (%)



Note: LFPR-labour force participation rate; WPR-worker population ratio; UR-unemployment rate.
Source: Computed from various years of the Employment and Unemployment Survey data and the Periodic Labour Force Survey unit-level data.

► विकास और रोजगार:

- वर्ष 2019 तक रोजगार वृद्धि दर स्थिर रही, उसके बाद सकारात्मक वृद्धि देखी गई।
- पूंजी गहनता के साथ-साथ श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई, जो पूंजी-गहन उत्पादन की ओर बदलाव का संकेतक है।
- वर्ष 2019 तक निम्न उत्पादकता वाले कृषि से उच्च उत्पादकता वाले गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार में बदलाव देखे गए।
- सुदृढ़ सकल मूल्य वर्धित वृद्धि के बावजूद विनिर्माण रोजगार में धीमी वृद्धि देखी गई।
- वर्ष 2000 के बाद से सेवा क्षेत्र भारत के विकास का प्राथमिक चालक रहा है, जो उच्च वेतन वाली औपचारिक नौकरी के अवसर पैदा करता है।

► युवा रोजगार की चुनौती:

- भारत जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन 2036 तक युवा आबादी में गिरावट की उम्मीद है।
- 2019 के बाद युवा श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि हुई, विशेषकर प्रामीण महिलाओं के बीच।
- अधिकांश युवा, वयस्कों की तुलना में कम वेतन और आय के साथ अनौपचारिक और निम्नतर व्यवसायों में लगे हुए हैं।
- युवा बेरोजगारी का उच्च स्तर पर दर्ज किया गया है, विशेषकर शिक्षित युवाओं में।
- उच्च शिक्षित युवाओं का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं है।
- कोविड महामारी के दौरान युवा श्रम बाजार संकेतक खराब हो गए लेकिन उसके बाद तेजी से सुधार भी हुआ।

► शिक्षा और युवा रोजगार:

- युवाओं के बीच शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, लेकिन असमानताएं अभी भी यथावत हैं।
- निचले स्तर पर शिक्षा की ओर वापसी हुई है, तथापि तकनीकी योग्यता और स्नातक डिग्री के लिए उच्चतम आधार बने हुए हैं।
- गैर-छात्र युवाओं, विशेषकर निम्न शिक्षा स्तर वाले युवाओं के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात में गिरावट देखी गई।
- यद्यपि शिक्षा को बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए संसाधन माना गया है, तथापि उच्च शिक्षित युवा मुख्य रूप से नियमित वेतनभोगी नौकरियों में कार्यरत हैं।

भारत रोजगार रिपोर्टें 2024 में प्रयुक्त रोजगार शब्दावली:

कार्यबल स्थिति (लेबर फोर्स स्टेटस):
यह किसी व्यक्ति की उस सक्रिय स्थिति को संदर्भित करता है, जैसा किसी सर्वेक्षण की निर्धारित अवधि के दौरान पाया जाता है। इस अवधि में किसी व्यक्ति को आम तौर पर तीन व्यापक कार्यबल स्थितियों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाता है:

रोजगार में लगा: आर्थिक गतिविधियों (काम) में सक्रिय रूप से संलग्न।
बेरोजगार: आर्थिक गतिविधियों (काम) में वर्तमान में संलग्न नहीं, लेकिन सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है या तत्काल उपलब्ध होने पर काम करने के लिए तैयार है।

श्रमबल से बाहर: न तो आर्थिक गतिविधियों (काम) में संलग्न है और न ही रोजगार की तलाश कर रहा है या काम करने के लिए उपलब्ध है।

सामान्य प्रमुख कार्य स्थिति (UPS):
सामान्य प्रमुख कार्य स्थिति किसी व्यक्ति की उस कार्य स्थिति को संदर्भित करती है, जैसा सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 365 दिनों के संदर्भ काल के दौरान पाई जाती है। सर्वेक्षण से पहले के 365 दिनों में किसी व्यक्ति ने किस कार्य स्थिति (मुख्य समय मापदंड) पर अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत किया है, उसे उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख कार्य स्थिति माना जाता है।

गौण आर्थिक गतिविधि स्थिति (SS):
गौण स्थिति वाले श्रमिक सर्वेक्षण साक्षात्कार से पहले के 365 दिनों में से कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए किसी आर्थिक गतिविधि में लगे होते हैं।

सामान्यतः मुख्य और गौण स्थिति (UPSS):
इस रोजगार स्थिति में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो सामान्य प्रमुख गतिविधि और गौण गतिविधि दोनों में लगे होते हैं।

चालू साम्राटिक स्थिति के अनुसार रोजगार (CWS):
सर्वेक्षण साक्षात्कार से पहले के सन्दर्भ सप्ताह (सात दिन) के दौरान किसी भी दिन कम से कम एक घंटे के लिए किसी आर्थिक गतिविधि में लगे सभी व्यक्ति इस समूह में शामिल होते हैं।

कार्यबल (श्रमिक या नियोजित व्यक्ति):
ऐसे व्यक्ति जो किसी आर्थिक गतिविधि में लगे थे या जो आर्थिक गतिविधि से जुड़े होने के बावजूद बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक अक्षमता, खराब मौसम, त्योहारों, सामाजिक या धार्मिक कार्यों या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से अनुपस्थित थे, उन्हें श्रमिक या नियोजित व्यक्ति माना जाता है। घर के खेत या गैर-कृषि गतिविधियों में किसी आर्थिक गतिविधि के संचालन में सहायता करने वाले अवैतनिक परिवार के सदस्यों को भी श्रमिक माना जाता है।

श्रमबल (लेबर फोर्स):
वे व्यक्ति जो या तो "काम कर रहे हैं या नियोजित हैं" या "काम की तलाश में हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं" या बेरोजगार हैं, मिलकर श्रमबल का गठन करते हैं।

बेरोजगार:
वे व्यक्ति जिन्हें काम न मिलने के कारण काम नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रोजगार कार्यालयों, विचौलियों, दोस्तों या रिश्तेदारों के माध्यम से या संभावित नियोजकों को आवेदन देकर काम की तलाश की है और वर्तमान कार्य परिस्थितियों और पारिस्थितिक के तहत काम करने की इच्छा या उपलब्धता व्यक्त की है, उन्हें "काम की तलाश करने या काम के लिए उपलब्ध" माना जाता है।

श्रमबल भागीदारी दर (LFPR):
यह दर श्रम आयु वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को इंगित करती है, जो श्रमबल में शामिल है।

कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR):
यह अनुपात जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाता है।

बेरोजगारी दर (UR):
इस दर को श्रमबल में मौजूद व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

► कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियाँ:

- कौशल-आपूर्ति और मांग के अंतर को समाप्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और एएलएमपी की आवश्यकता है।
- अन्य चुनौतियों में प्रशिक्षण का सीमित उपयोग, स्थानिक असंतुलन और प्रशिक्षण के लिए अपर्याप्त पारिश्रमिक जैसे करक शामिल हैं।

► नीतिगत एजेंडा: उद्यमिता विकास, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और रोजगार खोज सहायता कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Face to Face Centres





भारत ने अपने महासागर अधिकार क्षेत्र से परे कार्य अनुमति आवेदन किया है

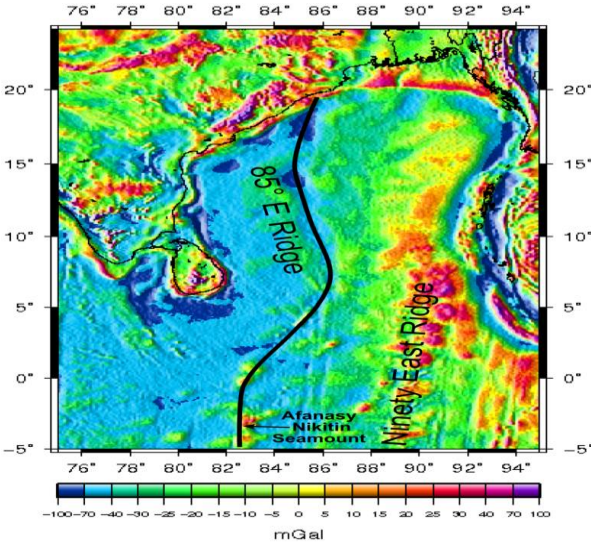
संदर्भ: भारत ने हाल ही में जमैका में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (आईएसबीए) को अपने अधिकार क्षेत्र से परे हिंद महासागर के दो बड़े क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति के लिए आवेदन किया है।

➤ पृष्ठभूमि:

- भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर हिंद महासागर के समुद्र तल में दो विशाल इलाकों का पता लगाने के लिए जमैका में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसबीए) में आवेदन किया है।
- श्रीलंका पहले ही अलग-अलग कानूनों के तहत इनमें से एक क्षेत्र, जिसे अफानसी निकितिन सीमाउंट (Afanasy Nikitin Seamount - AN Seamount) के नाम से जाना जाता है, पर अधिकार का दावा कर चुका है।
- भारत का आवेदन आंशिक रूप से उसी क्षेत्र में चीनी जहाजों द्वारा पूर्व-परीक्षण की रिपोर्टों से प्रेरित है।

➤ एएन सीमाउंट अन्वेषण:

- एएन सीमाउंट एक संरचनात्मक विशेषता है, जो मध्य भारतीय बेसिन में भारत के तट से लगभग 3,000 किमी दूर अवस्थित है।
- यह लगभग 400 किमी लंबा और 150 किमी चौड़ा है और लगभग 4,800 किमी की समुद्री गहराई से लगभग 1,200 मीटर तक विस्तृत है।
- पिछले दो दशकों में किए गए सर्वेक्षणों से कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और तांबे के समृद्ध भंडार का संकेत मिलता है।
- इच्छुक देशों को किसी भी निष्कर्षण से पहले अन्वेषण लाइसेंस के लिए आईएसबीए में आवेदन करना अनिवार्य होगा।



➤ खुले महासागर अधिकार:

- विश्व के लगभग 60% समुद्र खुले महासागर हैं, जहाँ कोई भी देश संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।
- सभी देशों को अपनी सीमाओं से 200 समुद्री मील तक महासागर में विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
- महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग किसी देश की महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर निर्णय लेता है।

➤ भारत का दावा:

- इस समय श्रीलंका ने बंगाल की खाड़ी के साथ विशेष मानदंडों के तहत 500 समुद्री मील तक का दावा किया है।
- भारत ने क्षेत्र में चीनी उपस्थिति के कारण अन्वेषण के लिए अपना दावा पेश किया है।
- उक्त संदर्भ में आईएसबीए ने श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत क्षेत्र में अन्वेषण के लिए अपने आवेदन के संबंध में भारत से स्पष्टीकरण मांगा है।

➤ आईएसबीए कार्यवाही:

- भारत के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अन्वेषण के अपने दावों के समर्थन में वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए।
- आईएसबीए ने भारत से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है, जिस पर अंतिम निर्णय इस साल के अंत में आने की उम्मीद है।
- भारत ने पॉलीमेटलिक सल्फाइड के लिए मध्य हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज का पता लगाने के लिए भी आवेदन किया है।

➤ महाद्वीपीय शेल्फ दावे:

- भारत ने अपनी सीमा से 350 समुद्री मील तक महाद्वीपीय शेल्फ पर दावा किया है।
- इसे पहले मध्य हिंद महासागर में दो अन्य बड़े बेसिनों के अन्वेषण अधिकार दिए जा चुके हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सीविजिल ऐप



सीविजिल भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

सीविजिल ऐप के बारे में:

- सीविजिल ऐप, "नागरिक सतर्कता" भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव मोबाइल एप्लिकेशन है।
- यह नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने और उसका समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- इस ऐप के माध्यम से, उपयोगकर्ता सीधे चुनाव आयोग को चुनावी कदाचार के फोटो और वीडियो जैसे साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन शिकायतें कर सकते हैं।

Face to Face Centres





27 March, 2024

	<ul style="list-style-type: none"> इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया की निगरानी में सक्रिय रूप से भाग लेने और चुनावों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। रिपोर्ट की गई घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए ऐप सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों से सीधे जोड़ता है। नागरिक ऐप के माध्यम से अति अल्प समय में राजनीतिक कदाचार की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। शिकायत दर्ज करने पर, नागरिकों को उनके मोबाइल उपकरणों पर वास्तविक समय में उनकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक अद्वितीय आईडी प्राप्त होती है। यह नागरिकों को 100 मिनट के भीतर कार्रवाई के आश्वासन के साथ उल्लंघनों की तुरंत रिपोर्ट करने का अधिकार देता है।
<p>एबेल पुरस्कार</p> 	<p>हाल ही में, 2024 का एबेल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ माइकल टैलाग्रैंड को संभावना सिद्धांत और फलन विश्लेषण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है जिसके गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं।</p> <p>एबेल पुरस्कार के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> एबेल पुरस्कार गणित का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829) के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 2003 में नॉर्वे की सरकार द्वारा की गई थी और इसे प्रसिद्ध नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कारों के आधार पर बनाया गया था। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 9 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन (लगभग 7 करोड़ रुपये) का नकद पुरस्कार मिलता है, जो इसे गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक बनाता है। यह पुरस्कार संभावना सिद्धांत, फलन विश्लेषण, गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी सहित विभिन्न गणितीय विषयों को शामिल करता है।
<p>भारतीय संविधान की छठी अनुसूची</p> 	<p>हाल ही में, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) द्वारा चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में शुरू की गई भूख हड़ताल कारगिल में शुरू हुई, जिसमें राज्य का दर्जा और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना शामिल है।</p> <p>भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम (उत्तरी कछार हिल्स जिला, कार्बी आंगलॉग जिला और बोडोलेंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला), मेघालय (खासी हिल्स जिला, जयंतिया हिल्स जिला, गारो हिल्स जिला), त्रिपुरा (त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट) और मिजोरम (चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला) में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। इसे 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, और यह संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) और क्षेत्रीय परिषदों (एआरसी) के निर्माण के प्रावधान शामिल हैं। यह आदिवासी भूमि और संसाधनों की रक्षा करना चाहता है उन्हें गैर-आदिवासी व्यक्तियों या समुदायों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करता है। राज्यपाल के पास स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में चिह्नित किए जाने वाले क्षेत्रों को निर्धारित करने का अधिकार है।
<p>कल्याणी के चालुक्य</p> 	<p>हाल ही में, तेलंगाना के एक मंदिर शहर गंगापुरम में, कल्याणी चालुक्य वंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है।</p> <p>कल्याणी के चालुक्यों के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है यह एक कन्नड़ राजवंश था जिसने 10वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। राजवंश की राजधानी कल्याणी थी जिसे अब बसवकल्याण के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्यों के वंशज थे जिन्होंने सदियों पहले इस क्षेत्र पर शासन किया था। राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक विक्रमादित्य VI थे, जिन्होंने 1076-1126 ईस्वी तक शासन किया। कल्याणी के चालुक्य अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते थे, जिसमें भित्ति चित्रों वाली गुफा मंदिर शामिल थे। यह मंदिर वेसर शैली का एक उदाहरण है जो द्रविड़ और नागर शैलियों का एक संयोजन है।
<p>स्टैघोर्न कोरल</p> 	<p>हाल ही में, थाईलैंड के रेयोंना प्रांत के पास मेन नाइ द्वीप के पानी में स्टैघोर्न कोरल देखे गए हैं।</p> <p>स्टैघोर्न कोरल के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> स्टैघोर्न मूंगा (एक्रोपोरा सर्विकोर्निस) एक शाखाओं वाला मूंगा है जिसकी सींग जैसी शाखाएं होती हैं जो 6.5 फीट (2 मीटर) तक लंबी हो सकती हैं। यह इंडो-पैसिफिक और अटलांटिक महासागरों में, आमतौर पर 25° उत्तर से 25° दक्षिण के बीच, गर्म, साफ, ऑक्सीजन युक्त पानी में पाया जाता है। स्टैघोर्न मूंगा कॉलोनिआं सफेद सिरों के साथ हल्के भूरे या सुनहरे भूरे रंग की होती हैं। यह बहामास, फ्लोरिडा और कैरेबियन में प्रवाल भित्तियों पर साफ, उथले पानी में पाया जाता है। यह रात्रिचर है और ज़ोप्लान्कटन नामक छोटे जलीय जंतुओं को खाने के लिए डंक मारने वाले जाल का उपयोग करता है। IUCN स्टैघोर्न कोरल को लगभग खतरे में मानता है।



27 March, 2024

सुर्खियों में स्थल

तुवालू

हाल ही में, एक अध्ययन से पता चला है कि तुवालू जलमग्न होने के खतरे का सामना कर रहा है और उसने अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है।

तुवालू (राजधानी: फुनाफुटी)

अवस्थिति: तुवालू, पश्चिम-मध्य प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र जो हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है और ओशिनिया नामक क्षेत्र का हिस्सा है।

भौगोलिक सीमाएँ: तुवालू की सीमा पूर्व में टोकेलौ, पश्चिम में सोलोमन द्वीपसमूह से संबंधित सांता क्रूज़ द्वीपसमूह, उत्तर में किरिबाती, उत्तर-पश्चिम में नाऊरू, दक्षिण में फिजी, दक्षिण-पूर्व में समोआ और वालिस और फ्यूच्यूना और दक्षिण-पश्चिम में वानुआतु से लगती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- इस द्वीप में तीन रीफ द्वीप (नानुमांगा, निउताओ और निउलाकिता) और छह सच्चे एटोल (फुनाफुटी, नानूमिया, नुई, नुकुफेटी, नुकुलेला और वैतुपु) शामिल हैं।
- फुनाफुटी सबसे बड़ा एटोल है और इसमें केंद्रीय लैगून के आसपास कई टापू शामिल हैं।
- तुवालू में उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु का अनुभव होता है जिसकी विशेषता पूरे वर्ष लगातार गर्म तापमान, उच्च आर्द्रता और अपेक्षाकृत स्थिर मौसम पैटर्न है।

अंतराष्ट्रीय संबंध: तुवालू संयुक्त राष्ट्र और प्रशांत द्वीप समूह फोरम सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।



POINTS TO PONDER

- हाल ही में समाचारों में रहा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? – **जम्मू और कश्मीर**
- किस शहर का पारंपरिक त्योहार जिसे गुलाल गोटा के नाम से जाना जाता है, हाल ही में खबरों में रहा है? – **जयपुर, राजस्थान**
- भारत और मॉरिटानिया के बीच उद्घाटन विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ हुआ? – **नौआकशॉट (Nouakchott)**
- हाल ही में किन देशों ने ऑस्ट्रेलिया की SSN-AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नया समझौता किया है? – **यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया**
- हाल ही में किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी का जीवित मानव में पहला प्रत्यारोपण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? – **संयुक्त राज्य अमेरिका**

Face to Face Centres

